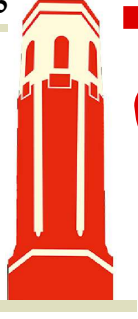


- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 279
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00



दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

उत्तराखण्ड पुलिस को मिला नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखण्ड पुलिस के नवीन ध्वज, प्रतीक चिन्ह, फॉर्मेशन साइन, ईसिग्निया, क्रैस्ट एवं सेरेमोनियल वर्दी का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'सत्यनिष्ठा से समृद्धि' थीम पर आधारित सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने उत्तराखण्ड पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत हुई श्रीमती शाहजहां जावेद खान एवं जगदीश चंद्र को प्रतीक चिन्ह अलंकरण कर पदोन्नति की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस के अधिकारियों एवं जवानों को नवीन गौरव चिह्नों के अनावरण पर बधाई देते हुए कहा कि पुलिस की पहचान को नया स्वरूप प्रदान करना केवल प्रतीकों और वर्दी में बदलाव नहीं, बल्कि पुलिस बल की गौरवशाली परंपराओं, शौर्य, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के मूल आदर्शों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि पुलिस के नए प्रतीक गौरव के साथ जिम्मेदारी का भी एहसास कराते हैं। इस नई पहचान का वास्तविक सम्मान तभी होगा, जब प्रत्येक नागरिक को पुलिस के व्यवहार में संवेदनशीलता, कार्यप्रणाली



◆ सीएम धामी ने किया नवीन गौरव चिह्नों का अनावरण

में दक्षता और कार्रवाई में निष्पक्षता दिखाई दे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखण्ड पुलिस को भी आधुनिक तकनीक से सुसज्जित, अधिक प्रशिक्षित, दक्ष एवं सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस का नवीन ध्वज वाक्य 'कर्म सत्यं शौर्य' कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और साहस का संदेश देता है। पुलिस के प्रत्येक अधिकारी और जवान को इन आदर्शों

को अपने आचरण एवं कार्यशैली में आत्मसात करना होगा। वर्दी का सम्मान आचरण से और जनता का विश्वास सेवा से मजबूत होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड पुलिस के नवीन गौरव चिह्नों का अनावरण विशेष महत्व रखता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि यह अवसर राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और

राष्ट्रसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के शुभारंभ पर कहा कि प्रदेश के विकास के साथ शासन व्यवस्था में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। विकास का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब सरकारी संसाधनों का सही उपयोग हो और आमजन को बिना किसी परेशानी के सरकारी सेवाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। भ्रष्टाचारमुक्त

शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने में सतर्कता विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करने के साथ उन खामियों को भी दूर करना आवश्यक है, जिनके कारण भ्रष्टाचार की संभावनाएं पैदा होती हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने और किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1064 पर दर्ज कराने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की भांति भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए संचालित हेल्पलाइन नंबर 1064 की भी नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यालय आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बात संवेदनशीलता से सुनने तथा उनके कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उत्तराखण्ड में ऐसी भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था का निर्माण करना है, जहां प्रत्येक नागरिक को सम्मान मिले, जनसेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न हो और जनता तथा शासन-प्रशासन के बीच विश्वास निरंतर मजबूत होता रहे। ▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दूसरे दिन भी रेस्क्यू जारी!

हमारे संवाददाता

चमोली। बदरीनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दूसरे दिन भी रेस्क्यू जारी है। शनिवार को डीजीसीए और जांच ब्यूरो की टीम हादसे के कारणों की जांच करेगी, जबकि मृतकों के परिजन भी पहुंचेंगे। बदरीनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दूसरे दिन रेस्क्यू अभियान जारी है। रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। मौसम साफ होने के साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ पुलिस की रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर तड़के ही रवाना हुई। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी ने कहा कि मौके पर मौजूद शवों को रेस्क्यू कर लाया जाएंगे। सेना सिग्नल कोर के जवान सुबह ही मौके पर पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि बीते दिन बदरीनाथ धाम से देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपैड के लिए रवाना हुआ था जो दो करीब बजे दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस दुर्घटना में दिल्ली के पायलट व कर्नाटक के पांच यात्रियों की मौत हुई है। बदरीनाथ से उड़ान भरकर पांडुकेश्वर में दुर्घटनाग्रस्त ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, हादसे के क्या कारण रहे, इसकी जांच आज होगी। बता दें कि पिछले दो दिनों से उत्तराखण्ड के मौसम में जोरदार परिवर्तन सामने आया। जिसमें लगभग सभी जिलों में बारिश व बर्फबारी के कारण हवाई तथा जमीनी यात्रा प्रभावित रही। ऐसे में बीते रोज हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें दिल्ली के पायलट व कर्नाटक के यात्री सवार थे।



दून वैली मेल

संपादकीय

95 साल बाद जातियों की गिनती

भारत में 95 साल बाद जातियों की गिनती का सवाल केवल जनगणना की प्रक्रिया में बदलाव नहीं है, बल्कि यह देश की राजनीति, सामाजिक व्यवस्था और सत्ता में हिस्सेदारी की बहस को नए सिरे से खड़ा करने वाला घटनाक्रम है। वर्ष 1931 के बाद पहली बार देशव्यापी जनगणना में सभी जातियों की गणना की जा रही है। स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गणना होती रही है, लेकिन सभी जातियों की व्यापक गणना नहीं हुई थी। अब करीब एक सदी बाद देश की जातिगत संरचना की नई तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। यह आंकड़ों का सवाल जरूर है, लेकिन इसके भीतर सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अवसरों की समानता का बड़ा प्रश्न छिपा है। जनगणना का दूसरा चरण 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलने की जानकारी सामने आई है। इस बार 40 सवाल पूछे जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल सरकार और राजनीतिक व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए कि क्या देश जातियों की संख्या जानने के बाद उन असमानताओं का हिसाब भी करेगा, जो पीढ़ियों से समाज के एक बड़े हिस्से को पीछे धकेलती रही हैं? जाति भारतीय समाज की वह सच्चाई है, जिसे राजनीतिक दल चुनाव के समय कभी स्वीकार करते हैं, कभी नकारते हैं और कभी अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। टिकट वितरण से लेकर मंत्रिमंडल गठन, सामाजिक समीकरणों से लेकर चुनावी घोषणाओं तक जाति की भूमिका दिखाई देती है। फिर भी जब जातियों की वास्तविक संख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति जानने की बात आती है, तो बहस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में उलझ जाती है। जाति का चुनावी गणित साधने वाली राजनीति के सामने अब यह चुनौती है कि वह सामाजिक न्याय के वास्तविक गणित से भी सामना करे। जातिवार गणना के समर्थकों का तर्क है कि जब तक विभिन्न समुदायों की वास्तविक संख्या और स्थिति का विश्वसनीय आकलन नहीं होगा, तब तक उनके लिए नीतियां बनाने और अवसरों की असमानता को दूर करने की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। यह तर्क महत्वपूर्ण है। आखिर जिस समाज की संरचना के बारे में पर्याप्त आंकड़े ही उपलब्ध न हों, उसकी समस्याओं का सटीक समाधान कैसे तैयार किया जा सकता है? लेकिन यहाँ एक और सावधानी जरूरी है। किसी जाति की आबादी अधिक होने का अर्थ यह नहीं कि वह सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न भी है। इसी तरह कम आबादी किसी समुदाय की वंचना का अपने आप में प्रमाण नहीं है। शिक्षा, रोजगार, आय, भूमि, स्वास्थ्य और सार्वजनिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के आंकड़ों के साथ जातिगत गणना का विश्लेषण होगा, तभी तस्वीर पूरी होगी। सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि किस जाति की आबादी कितनी है। सवाल यह भी होना चाहिए कि किस समुदाय के कितने बच्चे उच्च शिक्षा तक पहुंच पा रहे हैं, किन समूहों को रोजगार के अवसर कम मिल रहे हैं, किन क्षेत्रों में सामाजिक पिछड़ापन बना हुआ है और सरकारी योजनाओं का लाभ किन तक नहीं पहुंच पा रहा है। आबादी गिनना पहला कदम है। अवसरों की असमानता का हिसाब लेना अगला और कहीं अधिक कठिन कदम। जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने पर राजनीतिक दलों के लिए अपने सामाजिक आधार और प्रतिनिधित्व के दावों की समीक्षा से बचना आसान नहीं होगा। जो दल सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन्हें बताना होगा कि उनके संगठन, उम्मीदवारों के चयन और सत्ता में भागीदारी में यह सिद्धांत कितना दिखाई देता है, जो दल विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हैं, उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि विकास का लाभ समाज के अलग-अलग वर्गों तक किस अनुपात में पहुंचा है। यहां केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। उसे गणना की पद्धति, आंकड़ों की विश्वसनीयता, निजता की सुरक्षा और परिणामों के उपयोग को लेकर स्पष्टता रखनी होगी। विपक्ष को भी केवल आंकड़ों की मांग या सरकार की आलोचना तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे यह बताना होगा कि जातिवार आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की नीतियों में क्या बदलाव किए जाने चाहिए। जाति जनगणना को किसी एक दल की राजनीतिक जीत या हार के रूप में देखना भी गलत होगा। यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। यदि आंकड़े केवल चुनावी भाषणों, जातिगत ध्रुवीकरण और सत्ता के नए समीकरण बनाने में इस्तेमाल हुए, तो देश को आंकड़ों का भंडार तो मिलेगा, लेकिन सामाजिक न्याय की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं होगी। प्रस्तावित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर को संभावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अलग रखने की बात कही गई है। वहीं बर्फबारी प्रभावित लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए भी अलग व्यवस्था की जरूरत बताई जा रही है। इन परिस्थितियों में अलग समय-सारिणी प्रशासनिक दृष्टि से व्यावहारिक हो सकती है, लेकिन इसके पीछे के आधार और आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्य की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिकों को पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी दिखाई दे। राज्यों में समय का अंतर हो सकता है, लेकिन आंकड़ों की गुणवत्ता, गणना के मानक और परिणामों की राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीयता से समझौता नहीं होना चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चुनावी गतिविधियों या कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण किसी क्षेत्र की आबादी गणना से छूट न जाए। 95 साल बाद सभी जातियों की व्यापक गणना का अवसर देश को अपनी सामाजिक संरचना समझने का नया आधार दे सकता है। यह उन दावों की जांच का मौका भी है, जिनके सहारे राजनीतिक दल दशकों से विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व और कल्याण की बात करते आए हैं। मगर इस प्रक्रिया की सफलता केवल गणना पूरी होने या आंकड़े जारी होने से तय नहीं होगी। असली सवाल यह है कि जातियों की गिनती के बाद क्या सत्ता अपनी नीतियों का हिसाब देने को तैयार होगी? क्या आंकड़े उन बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का रास्ता खोलेंगे, जिन्हें अवसर नहीं मिले? क्या वे उन युवाओं के लिए रोजगार और प्रतिनिधित्व की बहस को मजबूत करेंगे, जो व्यवस्था में अपनी जगह तलाश रहे हैं? क्या सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की समस्याओं को चुनावी घोषणाओं से निकालकर ठोस नीतियों तक पहुंचाया जाएगा? जातियों की गिनती इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है, लेकिन सामाजिक न्याय की मंजिल नहीं। मंजिल नहीं आएगी, जब आंकड़ों के आधार पर अवसरों की खाई कम होगी, भेदभाव कमजोर पड़ेगा और हर नागरिक को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। यही 95 साल बाद होने वाली इस ऐतिहासिक कवायद की असली कसौटी है।

‘लोकतंत्र’ की लड़ाई में ‘नैरेटिव’

कार्यालय संवाददाता
देहरादून/नई दिल्ली। सियासत में लड़ाई केवल आरोप लगाने की नहीं, बल्कि जनता के बीच उन आरोपों का अर्थ तय करने की भी होती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के महाभियोग संबंधी कदमों के विरोध में भाजपा की प्रस्तावित आक्रामक रणनीति इसी राजनीतिक गणित की ओर इशारा करती है। वोट चोरी के आरोपों से विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करना चाहता है, जबकि भाजपा लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ के नारे के साथ पलटवार की जमीन तैयार कर रही है। दिल्ली में माक पार्लियामेंट और देशभर में पदयात्राओं तथा रैलियों की प्रस्तावित योजना को इसी व्यापक राजनीतिक लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा समझती है कि यदि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया पर उठाए सवालों को लगातार जनचर्चा के केंद्र में बनाए रखता है, तो बहस का दबाव सत्तापक्ष पर बढ़ सकता है। इसलिए जवाबी रणनीति का मकसद केवल आरोपों का खंडन करना नहीं, बल्कि विपक्ष की राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाकर बहस की दिशा बदलना भी है। दूसरी तरफ विपक्ष की कोशिश है कि चुनावी पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही का सवाल राजनीतिक विमर्श से बाहर न जाने पाए। यानी लड़ाई अब केवल वोट चोरी के आरोप और उसके जवाब की नहीं, बल्कि इस बात की है कि जनता लोकतंत्र के सामने असली चुनौती किसे मानती है।

भाजपा का लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ नारा विपक्ष के आंदोलन को राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश है। इसके जरिए पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि लोकतंत्र के नाम पर चलाए जा रहे आंदोलनों के उद्देश्यों और तरीकों पर भी सवाल उठने चाहिए। प्रस्तावित जनसभाएं, पदयात्राएं और माक पार्लियामेंट इस संदेश को संगठन से लेकर

◆वोट चोरी की काट में भाजपा का पलटवार
◆विपक्ष के नैरेटिव पर कब्जे की जंग हुई शुरु
◆भाजपा ने की जवाबी घेरेबंदी की पूरी तैयारी
◆राजनीतिक चुनौती संग जनमत की है लड़ाई

आम जनता तक पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं। लेकिन भाजपा के सामने एक राजनीतिक जोखिम भी है। यदि विपक्ष के आरोपों का जवाब तथ्यों के बजाय केवल नारों से दिया गया, तो बहस खत्म होने के बजाय और तीखी हो सकती है। चुनावी प्रक्रिया पर उठे सवालों का प्रभावी उत्तर तभी संभव है, जब संबंधित तथ्यों, नियमों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया जाए। राजनीतिक आक्रामकता समर्थकों को उत्साहित कर सकती है, लेकिन व्यापक जनविश्वास अर्जित करने के लिए प्रमाण और पारदर्शिता जरूरी हैं।

संयुक्त नागरिक संगठन ने दी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि

संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड को आज जनता के प्रति जवाबदेह, ईमानदार, कर्तव्य परायण, समर्पित नौकरशाही की जरूरत है जो राजनेताओं की गुलामी नहीं बल्कि जनाकांक्षाओं के अनुरूप सेवक के रूप में निष्पक्ष निर्णय ले सके। स्वतंत्रता सेनानी तथा देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल का स्पष्ट मानना था कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्य करने की आजादी और सवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए जिससे वह देश हित में निष्पक्ष निर्णय ले सके। प्रशासनिक अधिकारी नेताओं के नहीं संविधान के सेवक हैं, ये अहसास नौकरशाही को कराया जाना समय की मांग भी है।

ये उद्गार पटेल की 151 वी जयंती पर पटेल पार्क देहरादून में, संयुक्त नागरिक संगठन के तत्वाधान में पटेल की प्रतिमा के समक्ष आयोजित देशभक्त को देशभक्तों के श्रद्धासुमन कार्यक्रम में दून की सामाजिक संस्थाओं के प्रबुद्धजनों के थे जिन्होंने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कहे। वक्ताओं ने कहा सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता, मित्रता की भावनाओं को सुदृढ़ बनाते हुए विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों को लेकर गठित संस्थाओं के नेतृत्व को एकता के सूत्र में पिरोकर संयुक्त नागरिक संगठन विगत 10 वर्षों से सरदार पटेल के पदचिन्हों पर कार्यरत है जिस पर हमें गर्व है।

वक्ताओं ने कहा आजादी के बाद संविधान सभा में जब कुछ सदस्यों ने



अंग्रेजों की भारतीय सिविल सर्विस की निष्ठा पर आपत्तियां प्रगट की थी तब तत्कालीन गृहमंत्री पटेल ही थे जिन्होंने इन सेवाओं के पक्ष में अपनी विचारधारा को रेखांकित करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत बनाया।

पुष्पांजलि कार्यक्रम में डॉक्टर मुकुल शर्मा, कैप्टन पदमसिंह थापा, डा.एस स्वामी चंद्रा, मुकेश नारायण शर्मा, डॉ राकेश डंगवाल, मोहन सिंह खत्री, डा.महावीर सिंह बिष्ट, गिरीशचंद्र भट्ट, पद्मेश सिंह बर्थवाल, सुशील त्यागी, सुशील भंडारी, नरेश चंद्र कुलाश्री, राजीव खनसाली, दिनेश भंडारी, उमेश्वर सिंह रावत, अवधेश

विपक्ष के लिए भी चुनौती कम नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप गंभीर होते हैं। उन्हें राजनीतिक मंचों पर दोहराना आसान है, लेकिन विश्वसनीय साक्ष्यों के साथ स्थापित करना कठिन। यदि विपक्ष अपने आरोपों को ठोस तथ्यों से नहीं जोड़ पाया, तो भाजपा उसे राजनीतिक लाभ के लिए संस्थाओं पर सवाल उठाने वाला पक्ष बताने की कोशिश करेगी। देशव्यापी अभियान की तैयारी भाजपा के लिए संगठनात्मक शक्ति दिखाने का अवसर भी है। पदयात्राओं और रैलियों के जरिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सकती है, स्थानीय स्तर पर विपक्ष के आरोपों का जवाब पहुंचा सकती है और अपने समर्थकों के बीच एक साझा राजनीतिक संदेश तैयार कर सकती है।

यहां भाजपा की रणनीति का एक अहम पहलू दिखाई देता है। विपक्ष को अकेले राजनीतिक मैदान तय नहीं करने देना। यदि विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे पर आंदोलन खड़ा करता है, तो भाजपा समानांतर अभियान के जरिए मुकाबले को दोतरफा बनाना चाहती है। इससे मीडिया और सार्वजनिक बहस में विपक्ष के आरोपों के साथ भाजपा का जवाब भी प्रमुखता पा सकता है। हालांकि, सड़क पर भीड़ जुटाना और जनमत जीतना अलग-अलग बातें हैं। किसी अभियान की सफलता केवल रैलियों के आकार या नारों की तीव्रता से तय नहीं होती। जनता यह भी देखती है कि राजनीतिक दल उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं या

►► शेष पृष्ठ 7 पर

शर्मा, प्रकाश नागिया, शांति प्रसाद नौटियाल, पंकी बिष्ट, सुश्री गीता चौधरी, अंकित सिंह, डा.ऊर्जा आहूजा, वैद्य साक्षी मित्तल, पुनः आरंभ, कृष्ण गोदियाल, राजेंद्र श्रीवास्तव, नीरज उनियाल, गोविंद सिंह गोसाईं आदि शामिल थे। अंत में उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच की सुलोचना भट्ट के पति के निधन पर दो मिनट मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि भी दी गई।

समिति ने स्व. इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको याद किया

संवाददाता
देहरादून। नेताजी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। समिति के प्रभात डंडरियाल और आरिफ वारसी ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंदिरा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम प्रतिज्ञा लें कि हम आंतकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष प्रभात डंडरियाल, प्रमुख महासचिव आरिफ वारसी, संदीप गुप्ता, अनिल अग्रवाल, गुलाम मुस्तफा, इलियास कुरैशी, नितिन राठौड़, सुशील विरमानी, परवेज आलम, सहित अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आठवें वेतन आयोग में पुराने पेंशनर्स को शामिल करने की मांग, आंदोलन की चेतावनी

अल्मोड़ा(आरएनएस)। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आठवें वेतन आयोग में वर्ष 2०26 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। एसोसिएशन के सदस्यों ने वर्चुअल बैठक कर मांग की कि आठवें वेतन आयोग के दायरे में पेंशन पुनरीक्षण को भी शामिल किया जाए। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। बैठक में पेंशनर्स ने कहा कि अब तक गठित सभी वेतन आयोगों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के पुनरीक्षण को शामिल किया जाता रहा है। कर्मचारियों ने पूरी जिंदगी देश की सेवा की है। ऐसे में सेवानिवृत्ति के आधार पर पेंशनर्स को अलग-अलग श्रेणियों में बांटना उनके साथ भेदभाव है। एसोसिएशन ने मांग की कि आठवें वेतन आयोग को पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश दिए जाएं, ताकि सभी पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सके। बैठक में हेम चंद्र जोशी, मोहन चंद्र कांडपाल, किशोर चंद्र जोशी, आनंद सिंह बगड़वाल, पीएस सत्याल, गिरीश चंद्र जोशी, विपिन जोशी, बालादत्त कांडपाल, अनुजा साह, चंद्रशेखर सिंह सिराड़ी, चंद्रमणि भट्ट, रमा भट्ट, पुष्पा कैड़ा, सुनैना मेहरा, सोना जोशी, डॉ. जेसी दुर्गापाल, डॉ. अरूण पंत, डॉ. गोकुल सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह ऐठानी, आशा कर्नाटक, आशा पंत, मदन सिंह मेर, पूरन लाल साह, बलवंत सिंह बिष्ट, गिरीश चंद्र मल्होत्रा, धाराबल्लभ पांडेय और महेंद्र सिंह अधिकारी सहित अन्य पेंशनर्स शामिल रहे।

पूर्व विधायक ठुकराल ने दिया आंदोलन को समर्थन

रुद्रपुर(आरएनएस)। छतरपुर रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर निर्माण, रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों के ठहराव और दिनेशपुर-मटकोटा मार्ग के चौड़ीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने ग्रामीणों को समर्थन देते हुए उनकी मांगों को जनहित से जुड़ा बताया। उन्होंने शासन और संबंधित विभागों से समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि छतरपुर रेलवे फाटक पर जाम के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। दिनेशपुर-मटकोटा मार्ग की संकरी सड़क और भारी वाहनों की तेज रफ्तार से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। क्षेत्र में सड़क हादसों में कई लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और मृतकों के पात्र परिजनों को नियमानुसार मुआवजा देने की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने छतरपुर रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग करते हुए कहा कि इससे जाम की समस्या से राहत मिलेगी और विद्यार्थियों, मरीजों व आम लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने छतरपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई। साथ ही दिनेशपुर-मटकोटा मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराने पर जोर दिया। ग्रामीणों ने मार्ग पर भारी वाहनों की गति नियंत्रित करने, प्रमुख स्थानों पर गति सीमा के संकेतक लगाने और दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा उपाय करने की मांग की। प्रदर्शन में प्रधान जगदीप सिंह विर्क, आनंद सिंह असगोला, किशोर कुमार हाल्दार, भुवन शर्मा, विक्रम ज्वाला, शैलेन्द्र प्रताप सिंह, कन्हैया लाल, संदीप कुमार, जयप्रकाश, योगेश जोशी, राकेश बिष्ट, ललित बिष्ट, केरू मंडल और आनंद शर्मा आदि मौजूद रहे।

चौनलिया नवोदय विद्यालय में बच्चों को कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

अल्मोड़ा(आरएनएस)। सुरक्षित बचपन अभियान के तहत बुधवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, चौनलिया में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा की सचिव अनामिका सिंह के निर्देश पर आयोजित शिविर में अधिकार मित्र हेमा पांडे और पैनल अधिवक्ता भोले शंकर ने विद्यार्थियों को बच्चों के कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। शिविर में विद्यार्थियों को नालसा की बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना, 2०24 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2०12 के बारे में बताया गया। इसके साथ ही यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, असुरक्षित स्पर्श, शिक्षा एवं समानता के अधिकार और निःशुल्क कानूनी सहायता जैसे विषयों पर जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार की परेशानी या शोषण की स्थिति में सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 193० और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1०98 की जानकारी भी दी गई। अभियान से संबंधित पंफलेट वितरित कर बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य घनश्याम जोशी सहित पंकज शाही, पूरन पंत, रविशंकर फुलोरिया, नर्मल कोहली, नारायण गिरी, पंकज किरोला, गुंजन पांडे और अंजलि गंगोला आदि मौजूद रहे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की नई पटकथा

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में 2०27 के विधानसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक विकल्पों की दस्तक तेज होने लगी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की अदला-बदली के स्थापित राजनीतिक ढांचे में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हुए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने राज्य स्वराज पार्टी का शुभारंभ किया है। नये विकल्प का संकल्प कार्यक्रम के साथ शुरू हुई इस राजनीतिक पहल में पार्टी का चुनाव चिह्न हीरा भी जारी किया गया। पार्टी ने प्रदेश के विकास, जनहित और जनभागीदारी को अपनी प्राथमिकता बताया है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में असली सवाल नए दल के गठन का नहीं, बल्कि उस राजनीतिक खालीपन का है, जिसे भरने के दावे बार-बार किए जाते रहे हैं। राज्य गठन के आंदोलन ने जिस क्षेत्रीय स्वाभिमान, स्थानीय भागीदारी और पहाड़ के हितों की राजनीति को जन्म दिया था, वह सत्ता के गलियारों तक पहुंचकर व्यापक जनोद्देश में क्यों नहीं बदल सकी? और क्या राज्य स्वराज पार्टी इस अधूरे राजनीतिक विमर्श को नई दिशा दे पाएगी?

नई पार्टी का शुभारंभ ऐसे समय हुआ है, जब प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की रणनीति पर काम कर रही है और कांग्रेस सत्ता में वापसी की संभावनाएं तलाश रही है। इस बीच तीसरे विकल्प की नई कोशिश राजनीतिक समीकरणों में हलचल पैदा कर सकती है। हालांकि, उसे तत्काल भाजपा या कांग्रेस के लिए चुनौती मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। उसकी वास्तविक ताकत संगठन, नेतृत्व, उम्मीदवारों और जनसमर्थन से तय होगी। उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की कहानी राज्य गठन के साथ जुड़ी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने अलग राज्य की मांग को राजनीतिक स्वर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन के दौरान क्षेत्रीय आकांक्षाओं और स्थानीय अस्मिता को जो समर्थन मिला, वह स्वतंत्र राज्य की स्थापना के बाद स्थायी चुनावी शक्ति में तब्दील नहीं हो सका। इसके बाद भी कई राजनीतिक प्रयास हुए, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का

शिक्षकों ने नवनि्युक्त सीईओ का स्वागत किया

हल्द्वानी(आरएनएस)। जिले के नवनि्युक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र आर्य से प्राथमिक शिक्षक संगठन से जुड़े शिक्षकों ने भीमताल डायट परिसर में मुलाकात की। सीईओ बनने पर उनका स्वागत किया।

इस दौरान आर्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिले में एक आदर्श और गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण तैयार करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आश्चस्त किया कि शिक्षकों की सभी जायज समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षक संगठन नैनीताल के पूर्व जिला मंत्री डिकर सिंह पडियार, ओखलकांडा के ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल सिंह बिष्ट, सिद्धार्थ पंत, कविता पंत, डॉ. देवेंद्र सिंह भैसोड़ा, लक्ष्मण सिंह पडियार आदि मौजूद रहे।

संगठनात्मक विस्तार तथा राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी उनकी ताकत क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ी चुनौती बनी रही।

इसका अर्थ यह नहीं कि उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की जरूरत समाप्त हो गई है। रोजगार, पलायन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े सवाल आज भी राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। असली समस्या यह है कि इन मुद्दों पर असंतोष को एकजुट राजनीतिक विकल्प में बदलने

◆अब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने बनाई नई पार्टी
◆भाजपा-कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती का दावा
◆पुरानी राजनीतिक व्यवस्था मिलेगी एक नई चुनौती

के लिए निरंतर संगठन, स्पष्ट नेतृत्व और विश्वसनीय कार्यक्रम की जरूरत होती है। राज्य स्वराज पार्टी के सामने भी यही परीक्षा है। क्या वह केवल भाजपा-कांग्रेस के विकल्प की घोषणा करेगी, या इन दोनों दलों से अलग अपनी नीतियों और राजनीतिक कार्यशैली का ठोस खाका पेश करेगी? क्या उसका प्रभाव कुछ स्थानीय क्षेत्रों तक सीमित रहेगा, या वह पूरे प्रदेश में संगठन खड़ा कर पाएगी? इन सवालों के जवाब ही उसके राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेंगे।

पार्टी ने हीरे को अपने चुनाव चिह्न के रूप में प्रस्तुत किया है। चुनाव चिह्न मतदाताओं के बीच पहचान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में केवल प्रतीक के सहारे जनाधार तैयार नहीं किया जा सकता। इसके लिए ऐसा नेतृत्व चाहिए, जिसकी राजनीतिक विश्वसनीयता हो। ऐसा संगठन चाहिए, जो चुनाव के बाद भी जनता के बीच सक्रिय रहे और ऐसा कार्यक्रम चाहिए, जो प्रदेश की वास्तविक समस्याओं के समाधान की दिशा दिखाए। भाजपा और कांग्रेस के पास दशकों का संगठनात्मक अनुभव, स्थानीय नेताओं का नेटवर्क और चुनाव प्रबंधन की स्थापित व्यवस्था है। इनके मुकाबले

मेडिकल कॉलेज में बालिका को नहीं मिला रक्त, रेडक्रॉस ने उठाए सवाल

अल्मोड़ा(आरएनएस)। सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में 12 वर्षीय बालिका को रक्त उपलब्ध नहीं होने के कारण रात करीब 1० बजे रेफर किए जाने का मामला सामने आया है। रेडक्रॉस पदाधिकारियों का कहना है कि वे रक्तदाता लेकर अस्पताल पहुंचे थे, इसके बावजूद बालिका को रेफर कर दिया गया। मामले में रेडक्रॉस ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर जांच कराने और ब्लड बैंक की व्यवस्था में सुधार की मांग की है। जानकारी के अनुसार, उपचार के दौरान बालिका को रक्त की आवश्यकता पड़ी, लेकिन परिजनों को ब्लड बैंक से रक्त नहीं मिल सका। इसकी जानकारी मिलने पर रेडक्रॉस पदाधिकारी रक्तदाता लेकर अस्पताल पहुंचे। इसके बावजूद रात करीब 1० बजे बालिका को रेफर कर दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद

नई पार्टी को अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए कहीं अधिक मेहनत करनी होगी। उसे केवल असंतोष की राजनीति से आगे बढ़कर यह बताना होगा कि सत्ता मिलने पर वह शासन की प्राथमिकताओं में क्या बदलाव करेगी।

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज होना स्वाभाविक है। नई पार्टी का शुभारंभ इसी व्यापक चुनावी हलचल का हिस्सा है। मगर राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ना और लोकतांत्रिक विकल्प मजबूत होना एक ही बात नहीं है। विकल्प तभी सार्थक होता है, जब वह मतदाता के सामने नीतिगत स्पष्टता और जवाबदेही का नया मानक रखे। राज्य स्वराज पार्टी को अब अपना नेतृत्व, संगठनात्मक ढांचा, चुनावी रणनीति और प्रदेश के प्रमुख मुद्दों पर नीतिगत दृष्टिकोण स्पष्ट करना होगा। उसे बताना होगा कि पहाड़ में पलायन रोकने, युवाओं को रोजगार देने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने तथा स्थानीय संसाधनों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए उसके पास क्या ठोस योजना है।

उत्तराखंड की राजनीति में तीसरे विकल्प की गुंजाइश पर बहस नई नहीं है। नई बात तभी होगी, जब कोई दल इस बहस को जमीनी संगठन और विश्वसनीय राजनीतिक कार्यक्रम में बदल सके। राज्य स्वराज पार्टी ने हीरा चुनाव चिह्न के साथ राजनीतिक मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। लेकिन 2०27 की चुनावी कसौटी पर उसकी चमक का फैसला नारों से नहीं, जनसमर्थन से होगा। भाजपा और कांग्रेस के बीच जगह बनाना चुनौती है, मगर उससे बड़ी चुनौती जनता को यह विश्वास दिलाना है कि नया विकल्प केवल सत्ता के समीकरण बदलने नहीं, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति की कार्यशैली बदलने आया है। यही वह सवाल है, जिसका जवाब राज्य स्वराज पार्टी को अपने संगठन, नीतियों और जनता के बीच काम से देना होगा। वरना उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की कहानी में एक नया नाम तो जुड़ जाएगा, लेकिन राजनीति के पुराने समीकरण जस के तस रहेंगे।

मेडिकल कॉलेज में बालिका को नहीं मिला रक्त, रेडक्रॉस ने उठाए सवाल

आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। रेडक्रॉस पदाधिकारियों ने पूछा कि रक्तदाता उपलब्ध कराने का प्रयास किए जाने के बावजूद बालिका को रेफर क्यों करना पड़ा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर रेफर किए जाने के कारणों का पता लगाने और संबंधित चिकित्सकों व ब्लड बैंक की भूमिका की समीक्षा करने की मांग की। पदाधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि ब्लड बैंक में रक्त लेने के लिए मरीजों के तीमारदारों से रक्तदाता की व्यवस्था करने को कहा जाता है।

उनका कहना है कि आपात स्थिति में इससे मरीज के परिजनों की परेशानी बढ़ सकती है। रेडक्रॉस ने मांग की कि ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता, रक्तदाताओं के समन्वय और आपातकालीन मरीजों को समय पर रक्त मुहैया कराने की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए।

स्क्रीन से सिरदर्द हो रहा है? इन 5 तरीकों से पाएं राहत

आजकल स्क्रीन से जुड़े काम करना आम हो गया है। चाहे वह ऑफिस का काम हो या घर का, हम सभी लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक स्क्रीन देखने से सिरदर्द हो सकता है? हां, यह सच है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और कारगर उपाय बताएंगे, जिनसे आप स्क्रीन से जुड़े काम करते समय सिरदर्द से बच सकते हैं।

स्क्रीन की चमक को करें सही : अपनी स्क्रीन की चमक को सही मात्रा में सेट करें। अगर चमक बहुत ज्यादा होगी तो आंखें जल्दी थक जाती हैं और इससे सिरदर्द हो कता है, वहीं अगर चमक कम होगी तो भी आंखों को तनाव होता है। इसे संतुलित रखने के लिए स्क्रीन की चमक को अपने कमरे की रोशनी के अनुसार सेट करें। इससे आपकी आंखें आराम महसूस करेंगी और सिरदर्द की संभावना कम होगी।

ब्रेक लेना है जरूरी : लंबे समय तक लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर दबाव पड़ता है, जिससे सिरदर्द हो सकता है। इसलिए हर 2० मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है। इस ब्रेक के दौरान आंखों को बंद करें या थोड़ी देर टहलें, इससे आपकी आंखें आराम करेंगी और सिरदर्द की संभावना कम होगी। ब्रेक लेने से न केवल आपकी आंखों को राहत मिलेगी बल्कि आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। यह आदत आपको लंबे समय तक आरामदायक अनुभव दिलाएगी।

सही रोशनी का रखें ध्यान : काम करने वाली जगह पर सही रोशनी होना बहुत जरूरी है। बहुत तेज या बहुत कमजोर रोशनी दोनों ही आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ऐसी रोशनी का उपयोग करें जो न तो बहुत तेज हो और न ही बहुत कमजोर, बल्कि संतुलित हो। इसके लिए आप सामान्य बल्बों की बजाय एलईडी बल्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा और सिरदर्द की संभावना भी कम होगी।

स्क्रीन प्रोटेक्टिव चश्मे पहनें : अगर आपको अक्सर स्क्रीन से सिरदर्द होता है तो स्क्रीन प्रोटेक्टिव चश्मे पहनना एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये चश्मे आपकी आंखों को हानिकारक नीली रोशनी से बचाते हैं और आंखों को आराम पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये चश्मे आपकी नजर को भी साफ रखते हैं, जिससे आप लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के काम कर सकते हैं। इन्हें पहनकर आप सिरदर्द से भी बच सकते हैं और अपने काम में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

सही फर्नीचर का करें इस्तेमाल : काम करने वाली कुर्सी और टेबल का सही चयन करना भी जरूरी है। कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी पीठ को सहारा दे सके और टेबल ऐसी होनी चाहिए जो आपकी स्क्रीन के स्तर पर हो ताकि गर्दन पर दबाव न पड़े। सही फर्नीचर का इस्तेमाल करने से न केवल आपका सिरदर्द कम होगा बल्कि आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इन सरल उपायों को अपनाकर आप स्क्रीन से जुड़े काम करते समय सिरदर्द से बच सकते हैं।

सावन के दौरान एयर फ्रायर में बनाएं ये त्यंजन, तुरंत हो जाएंगे तैयार

हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व है। इस दौरान कई लोग व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान खाने-पीने का खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप भी सावन के दौरान व्रत रखते हैं और रोजाना क्या खाएं? इस सवाल से परेशान रहते हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे एयर फ्रायर व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाना मुश्किल नहीं है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

आलू के चिप्स : सबसे पहले आलू को छीलकर पतले-पतले काट लें, फिर इन्हें पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद इनसे अतिरिक्त पानी निकालकर इन्हें एक कटोरे में डालें और इसके साथ सेंधा नमक, काली मिर्च और देसी घी मिलाएं। अब आलू के टुकड़ों को एयर फ्रायर में डालकर 18० डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए पकाएं। इसके बाद आलू के चिप्स को एक कटोरे में निकालकर इनमें थोड़ा नींबू का रस डालकर इन्हें परोसें।

साबूदाने के ढोकले : सबसे पहले साबूदाने को 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगोएं, फिर भीगे हुए साबूदाने को एक बर्तन में डालकर पीस लें। अब मिश्रण को एक कटोरे में डालकर उसमें अदरक का पेस्ट, सेंधा नमक और नींबू का रस मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को 2-3 मिनट के लिए फेंटे। अब मिश्रण को एक घी लगे बर्तन में डालकर एयर फ्रायर में 15 मिनट के लिए रखें। आखिर में ढोकले पर सरसों का तड़का लगाकर इसे परोसें।

साबूदाना टिकी : इसके लिए सबसे पहले साबूदाना, आलू, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, सेंधा नमक और नींबू के रस को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिकियां बनाकर इन्हें एयर फ्रायर में रखें। इसके बाद इसे 18० डिग्री सेल्सियस पर 1० मिनट तक पकाएं। इसके बाद गर्मागर्म टिकियों को बाहर निकालकर इन्हें परोसें। इस तरह की टिकियां स्वादिष्ट होती हैं और व्रत के लिए उपयुक्त भी।

शकरकंद के चिप्स : सबसे पहले एयर फ्रायर को पहले से गर्म करें, फिर उसमें छिली और पतली कटी हुई शकरकंद, स्वादानुसार सेंधा नमक, थोड़ा तेल और काली मिर्च पाउडर डालकर 15 मिनट के लिए एयर फ्रायर में रखें। इसके बाद शकरकंद के चिप्स को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें, फिर इन्हें किसी डिब्बे में भरकर रख लें। यह एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प है।

मथुरा की बेटी नीलम सिरोही की ऐतिहासिक सफलता : विश्व कुश्ती में रजत पदक से रोशन हुयी ब्रजभूमि

24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अस्ताना(कजाकिस्तान) में आयोजित हो रही सीनियर विश्व चैम्पियनशिप में आयोजन हो रहा है। ब्रजभूमि की माटी ने सदियों से ऐसे वीरों और महान खिलाड़ियों को जन्म दिया, जिसने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और अदम्य साहस से देश-दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है। इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मथुरा जिले के फैचरी गांव की बेटी नीलम सिरोही ने सीनियर विश्व चैम्पियनशिप में 5० किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर न केवल ब्रज का बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है।

नीलम सिरोही विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला पहलवान हैं। इससे पहले 2०21 में ओस्लो में 57 किलोग्राम भार वर्ग में अंशु मलिक ने रजत पदक जीता था। इस विश्व चैम्पियनशिप में नीलम सिरोही ने राउंड ऑफ 16(प्री-क्वार्टर फाइनल) में बेलारूस की नतालिया वराकिना को 6-० से हराया। क्वार्टर फाइनल में रूसी खिलाड़ी एलिजावेता स्मिरनोवा के चोटिल होकर हटने के कारण वॉकऑवर मिला। सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की जेनेप बयोनोवा का 7-3 से हराया। जेनेप बयानोवा ने हाल में सम्मन्न हुए एशियाई खेल 2०26 आईची-नागोया में भारत की दीपांशी को 11-4 से हराकर 5० किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। हालांकि नीलम सिरोही फाइनल में जापान की महान खिलाड़ी युई सुसाकी से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

युई सुसाकी बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं उन्होंने पाँचवीं बार विश्व चैम्पियनशिप जीता। इससे पहले उन्होंने 2०2० टोक्यो ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीता। 2०24 पेरिस ओलम्पिक में उन्होंने कांस्य पदक



◆ललित शर्मा

जीता था। इससे पहले नीलम सिरोही ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं।

नीलम सिरोही ने 2०17 में जुनियर वर्ग में कैडेट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप एथेंस में कांस्य पदक जीता था। 2०23 में एशियाई 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2०25 बुडपेस्ट रैंकिंग सीरिज में कांस्य पदक जीता। 2०25 उलानबटोर ओपन में कांस्य पदक जीता और 2०26 में जाग्रेव ओपन रैंकिंग सीरीज क्रोएशिया में रजत पदक जीता। 2०23 के राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता। इसी विश्व चैम्पियनशिप में नीलम सिरोही के अलावा एक और महिला पहलवान काजल ढोचक ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता।

नीलम सिरोही द्वारा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतना मथुरा और संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण उपलब्धि है। अन्तर्राष्ट्रीय कुश्ती में इतने वर्षों बाद मथुरा और ब्रजक्षेत्र के किसी खिलाड़ी ने हासिल की है। इससे पहले कैप्टन मुख्तियार पहलवान ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1966, 197० स्वर्ण पदक जीते थे। तथा 197० के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था।

ब्रज की मेट की कुश्ती आज अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ गयी हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि ब्रज क्षेत्र

में कुश्ती की दशा और दिशा सुधारने के लिए प्रशासन द्वारा ठोस एवं महत्पूर्ण कदम उठाये जाएं। यहां के अखाड़ों का विकास आधुनिक पद्धति पर किया जाए पहलवानों को आधुनिक प्रशिक्षण एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा उभरती हुई प्रतिभाओं को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि कुश्ती के हृदय-स्थल ब्रज क्षेत्र से नई प्रतिभाएं उभरकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें और ब्रजभूमि की गौरवशाली कुश्ती परंपरा को पुनः नई ऊँचाइयों तक पहुंचा सके। नीलम सिरोही की यह ऐतिहासिक उपलब्धि लाखों युवाओं विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह सफलता साबित करती है कि यदि ईमानदारी, लगन, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाए जाएं, तो छोटे से गांव की बेटी भी विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकती है। नीलम सिरोही ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर मथुरा और संपूर्ण ब्रज क्षेत्र की कुश्ती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। अब समय आ गया है कि मथुरा और ब्रज क्षेत्र में महिला कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक महिला अखाड़ों की स्थापना की जाए।

बेटियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाएं, आर्थिक सहयोग और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए, ताकि नीलम सिरोही जैसी अनेक बेटियां कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढ़कर ब्रजभूमि के साथ-साथ पूरे देश का नाम रोशन करें। नीलम सिरोही की सफलता ब्रज की बेटियों के लिए एक नई राह खोलेगी। संपूर्ण ब्रजवासी अपनी बेटी नीलम सिरोही की उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं और अपनी बेटी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

शब्द सामर्थ्य -074

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

- रूचिकर लगने वाली, रूचि के अनुकुल, चुनी हुई
- राजाओं के बैठने का आसन
- श्रमिक
- कार्य, काज
- वाद्ययंत्र आदि बजाने वाला
- सहारा, सहायक वस्तु
- शर्म, लाज, हया
- मकखन, माखन
- श्रीमती राबड़ी देवी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं
- चंद्रमा, रजनीश, चांद
- पुस्तक

ऊपर से नीचे

- पंद्रह दिन का समय, शुक्ल या कृष्ण पक्ष
- आग बुझाने की मशीन
- हिंदु विवाहित स्त्री के मांग में भरने का लाल चूर्ण
- पराजय, माला
- मुंह ढकने का कपड़ा, घुंघट
- चंदन, दक्षिण का

- अवधि, समय
- तर्क वितर्क और कहा-सुनी, जबानी झगड़ा
- सूरत, आकार
- झुका हुआ, नत

- एक पर्वत
- व्यवस्थित करना, सजाना, स्वभाव आदि का परिष्कार, शुद्ध संबंधी कृत्य
- विशालता, बड़प्पन, महान होने का भाव
- अड़चन, रुकावट
- जमीन के अंदर गहरा और लंबा रास्ता, अच्छे रंग का
- बेवकूफ, मूर्ख, अहमक
- औसत के हिसाब से
- कृषक
- अधिक, ज्यादा

1		2		3	4		5	
		6					7	8
9						10		
		11			12			
	13			14				
15		16						17
				18		19		
		20				21		
	22			23				

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 73 का हल

ज	ल		आ	वा	जा	ही		
मा		खू	ब		दू	र	स्थ	
ना	दा	न		सा	ग		ल	क्ष्य
12	न	ख		त	र	ल		
12	वी	रा	न			च	ट	क
17	र	ब		आ	ज	क	ल	
		17	21	आ	ग	19	दा	ना
33	अ	ग	र	म	ग	र		क्रो
भा	भी		ती	न			व	ध

हाउसफुल 4' के 7 साल पूरे होने पर कृति खरबंदा ने याद किया अपना शाही अंदाज!

2019 में रिलीज हुई फिल्म हाउसफुल 4' बॉलीवुड की लोकप्रिय कॉमेडी फ्रेंचाइजी की यादगार फिल्मों में से एक है। फिल्म के सात साल पूरे होने के मौके पर अभिनेत्री कृति खरबंदा ने इससे जुड़ी यादें ताजा की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नॉस्टैल्जिक पोस्ट साझा करते हुए फिल्म के साथ अपने जुड़ाव को याद किया है। फिल्म की सालगिरह के मौके पर कृति ने एक एआई से तैयार किया गया वीडियो साझा किया है, जिसमें फिल्म से उनका लुक नजर आ रहा है। इस वीडियो ने प्रशंसकों को एक बार फिर हाउसफुल 4' की दुनिया की याद दिला दी है। इसके साथ ही अभिनेत्री ने एक भावुक नोट लिखा है, फिल्म, इस अनुभव, पूरी टीम और बेशक हमारे दर्शकों के लिए आभारी हूँ! ?? उनके इस संदेश ने फिल्म से जुड़े अनुभवों, साथ काम करने वाले लोगों और दर्शकों से मिले प्यार के प्रति उनकी कृतज्ञता को जाहिर किया है। हाउसफुल 4' में कृति खरबंदा दोहरी भूमिका में नजर आई थीं, जहां उन्होंने अलग-अलग दौर के दो किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया था। फिल्म में उनका शाही अंदाज खास आकर्षण का केंद्र रहा। पारंपरिक परिधानों, खूबसूरत आभूषणों और राजसी स्टाइलिंग से सजे उनके लुक ने दर्शकों का ध्यान खींचा। फिल्म की दो अलग-अलग समयावधियों में उनके किरदारों के लुक और व्यक्तित्व में नजर आया अंतर भी फिल्म की खासियतों में शामिल रहा।



सात साल बाद कृति की यह पोस्ट पुरानी यादों को ताजा करने के साथ फिल्म का हिस्सा बनने के उनके अनुभव का जश्न मना रही है। अपने एआई वीडियो और दिल छू लेने वाले संदेश के जरिए अभिनेत्री ने न सिर्फ अपने फिल्मी सफर के इस खास पड़ाव को याद किया है, बल्कि उस टीम व दर्शकों के प्रति आभार भी जताया है, जिन्होंने इस सफर को यादगार बनाया।

रश्मिका ने 100 बार शादी के लिए पूछा!

विजय देवरकोंडा इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं और इसकी वजह उनकी हालिया रिलीज फिल्म रणबाली' नहीं बल्कि उनका एक बयान है। दरअसल, विजय देवरकोंडा अपनी पत्नी रश्मिका मंदाना के साथ करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण सीजन 9' में आए थे। इस शो में उन्होंने रश्मिका संग शादी की वजह बताई जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शो में करण जौहर ने मैरिज प्रपोजल के बारे में पूछा, तब उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने रश्मिका से 100 बार शादी के लिए पूछने के लिए कहा था और उन्होंने करीब एक साल तक उनसे शादी के लिए पूछा। कई लोग विजय को रोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, रश्मिका विजय से प्यार करती हैं, लेकिन विजय खुद से प्यार करते हैं। वहीं, कुछ कह रहे हैं कि रश्मिका को थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। यही नहीं, कुछ लोग विजय को रेड फ्लैग बुला रहे हैं। कुछ यह भी कह रहे हैं कि विजय ने रश्मिका को शर्मिंदा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक्टर को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है।

90एस के सीरियलों पर भारी पड़ा था दूरदर्शन का शो!

दूरदर्शन ने हमें कई ऐसे टीवी शोज दिए हैं जिनको आज तक भुला पाना मुश्किल है। इन सीरियलों में एक अलग तरह की कशिश थी जिनकी कहानी कहीं न कहीं हमारे जहन में बसी है। आप इन्हें आराम से परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। इनमें भारतीय संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और आम आदमी की जिंदगी की झलक देखने को मिलती थी। इन्हीं में से एक था साल 1994 में आया टीवी शो शांति एक घर की बुनियाद। इसमें मंदिरा बेदी ने लीड रोल निभाया था। दोपहर 2.30 बजे जब ये टीवी पर आता था तो लोग अपना सारा कामकाज छोड़कर आंख गड़ाकर बैठ जाते थे। कहानी की मुख्य किरदार शांति (मंदिरा बेदी) एक महत्वाकांक्षी और निडर पत्रकार के बारे में है। शो में मंदिरा बेदी का किरदार शांति अपनी मां के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने निकलती है। वो भी एक रसूखदार परिवार से। कहानी में शांति अपनी मां तुलसी के साथ हुए दुष्कर्म के पीछे छिपे सच को सामने लाने के लिए पूरी कोशिश करती है। इस सीरियल से मंदिरा बेदी को काफी लोकप्रियता मिली। उनके शानदार अभिनय और उनकी तीर वाली वाली बिंदी ने उस दौर में इस किरदार को घर-घर में पहचान दिलाई। इसके लगभग 780 एपिसोड प्रसारित हुए थे। इस शो ने पहली बार भारतीय टीवी पर एक आत्मनिर्भर और विद्रोही महिला की छवि पेश की थी। शांति' सिर्फ एक टीवी शो नहीं बल्कि 90s के बच्चों और परिवारों की यादों का हिस्सा था जिसे देखकर वो दोपहर में स्कूल से आने के बाद खाना खाते थे।

जावेद अख्तर ने विज्ञान और तकनीक को कला के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर दिया जोर

वरिष्ठ पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उदार कलाओं (लिबरल आर्ट्स) के साथ जोड़ने के महत्व पर जोर दिया है। जावेद अख्तर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ उदार कलाओं (लिबरल आर्ट्स) के समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इतिहास, साहित्य, कविता और चित्रकला जैसे विषयों का ज्ञान एक संतुलित व्यक्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। अख्तर ने आईएनएस से बातचीत में कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानव प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कला और मानवीय विषयों की समझ ही इंसान को कंप्यूटर और रोबोट से अलग बनाती है।

उन्होंने कहा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन लिबरल आर्ट्स की भी कुछ समझ होना जरूरी है। यही एक इंसान और कंप्यूटर या रोबोट के बीच का अंतर है।

गीतकार ने आगे कहा कि लोगों को अपने-अपने क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लिबरल आर्ट्स का अध्ययन करने वालों को भी विज्ञान की बुनियादी समझ होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, इसी तरह विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लिबरल आर्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। इतिहास, साहित्य, कविता, चित्रकला और लोक कलाएं, इन सबकी समझ जरूरी है। ज्ञान को इस तरह अलग-अलग खांचों में बांटना सही नहीं है।



पटकथा लेखक, गीतकार और कवि के रूप में पहचान रखने वाले जावेद अख्तर लंबे समय से भारतीय सिनेमा और साहित्य से जुड़े रहे हैं।

जावेद अख्तर को प्रसिद्ध पटकथा लेखन जोड़ी सलीम-जावेद के सदस्य के रूप में व्यापक पहचान मिली। सलीम खान के साथ उनकी इस जोड़ी ने जंजीर' (1973), दीवार' (1975), शोले' (1975) और मिस्टर इंडिया' (1987) जैसी कई ऐतिहासिक हिंदी फिल्मों की पटकथाएं लिखीं, जिन्होंने बॉलीवुड की कहानी कहने की शैली पर गहरा प्रभाव छोड़ा।

बाद में उन्होंने एक प्रतिष्ठित गीतकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई और सिलसिला', 1942= ए लव स्टोरी', बॉर्डर', रिफ्यूजी' और लगान' जैसी फिल्मों के लिए यादगार गीत लिखे।

सिनेमा के अलावा अख्तर एक प्रतिष्ठित उर्दू कवि भी हैं। उनकी चर्चित काव्य कृतियों में तरकश' शामिल है। भारतीय सिनेमा और साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अलावा 1999 में पद्म श्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है।

श्रीदेवी काम को लेकर बेहद अनुशासित थीं: हेतल यादव



अभिनेत्री हेतल यादव ने अपने करियर की शुरुआत कोरियोग्राफर के तौर पर की थी। इस दौरान उन्होंने इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के साथ भी काम किया है, जिनमें दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी का नाम भी शामिल है। हेतल यादव ने श्रीदेवी के साथ अपने काम करने के अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि उनसे उन्होंने

क्या कुछ सीखा। अभिनेत्री ने बताया कि वह खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि लंबे करियर में इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। अभिनेत्री ने कहा, मैंने अपने लंबे करियर में कई क्षेत्रीय फिल्मों में काम करने के साथ-साथ कमर्शियल हिंदी फिल्मों में भी किया है। हालांकि एक एक्टर के तौर पर मैंने

श्रीदेवी के साथ काम नहीं किया है, लेकिन एक प्रोड्यूसर के तौर पर बोनी कपूर की कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने कहा, फिल्म पुकार के गाने की शूटिंग के दौरान मेरी मुलाकात श्रीदेवी से हुई थी और उनसे बातचीत करने का मौका मिला था। उस समय शायद उनकी बड़ी बेटी जाहवी कपूर हो चुकी थी। मैंने श्री देवी में एक खासियत देखी कि वे अपने काम को लेकर बहुत अनुशासित और ईमानदार थीं और जो भी लोग उनके करीब हैं, वे इस बात से भली-भांति वाकिफ होंगे। हमारी इंडस्ट्री में आज ऐसे लोग कम ही देखने को मिलते हैं।

अभिनेत्री हेतल यादव ने आगे इंडस्ट्री के बदलाव पर भी बात की। उनका मानना है आज के मुकाबले में पहले के समय नए एक्टर्स को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था।

उन्होंने कहा, उस समय एक अलग तरह का संघर्ष था और अलग तरह की चुनौतियां थीं, हालांकि आज के समय में भी अलग तरह की चुनौतियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इन सबमें ओटीटी, टेलीविजन या फिल्मों में आना बहुत आसान हो गया है। अब नए एक्टर्स के लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शकों के दिलों में जगह बनाना आसान हो गया है, खासकर उन लोगों को लिए जिनके पास संसाधन नहीं हैं। आज बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पहले नहीं थीं।

बगेश्वर में तीन से पांच नवंबर तक सरस मेले का आयोजन

बागेश्वर(आरएनएस)। ग्राम्य विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत तीन से पांच नवंबर तक नुमाइशखेत मैदान में सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना तथा आजीविका के साधनों को सशक्त बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि मेले में कुल 35 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें उद्योग, कृषि एवं उद्यान विभाग के साथ ही ग्रामोत्थान मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना तथा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री की जाएगी। मेले के माध्यम से महिला समूहों को अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार और विपणन के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा, जिससे उनके उत्पादों को व्यापक पहचान मिल सकेगी और आय के नए अवसर सृजित होंगे। मेले के दौरान स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इनमें लोकगीत, लोकनृत्य, मेहंदी एवं एपण प्रतियोगिताओं के साथ विभिन्न खेल गतिविधियां शामिल रहेंगी। इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय लोक संस्कृति, पारंपरिक कला एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मोहनपुर में लग रहे डीसीयू को हटाने के निर्देश

चम्पावत(आरएनएस)। एसडीएम प्रमोद कुमार ने मोहनपुर में लगाए जा रहे गैसोनेट के डीसीयू (डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट) को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने बैठक में बिना एनओसी के प्लांट लगाए जाने पर विरोध जताया। टनकपुर तहसील में एसडीएम प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बिना एनओसी के डीसीयू लगाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि प्लांट लगाने में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। गैसोनेट के प्रतिनिधियों ने गैस स्टोरेज और कास्केड परिवहन से जुड़े सुरक्षा मानकों की जानकारी दी, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और अग्निशमन विभाग के अधिकारी इन दावों से संतुष्ट नहीं दिखे। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एसडीएम ने डीसीयू को तत्काल आबादी क्षेत्र से हटाने के निर्देश दिए। प्रधान राधिका चंद और जिला पंचायत उपाध्यक्ष पुष्पा विश्वकर्मा ने कहा कि यह लोगों की जान से खेलने जैसा है। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में तहसीलदार पंकी आर्या, राजस्व निरीक्षक राकेश कुमार, अग्निशमन विभाग के अमर सिंह अधिकारी, सभासद शैलेंद्र सिंह, मोहन भट्ट, सुरेश नाथ, जानकी खर्कवाल, पुष्पा भट्ट और कुसुम खर्कवाल आदि मौजूद रहे।

सू- दोकू क्र.074									
	2			6				1	
3			4				2		
								6	
6					4				
	9		5			6			1
4		3			9				2
	8		2				7		
1		2		4		9			6
नियम		सू-दोकू क्र.73 का हल							
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।		8	7	6	9	5	1	2	3
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।		1	3	9	2	8	4	5	6
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।		4	5	2	3	7	6	9	1
		2	8	5	4	6	7	1	9
		3	1	7	8	9	2	4	5
		6	9	4	1	3	5	7	8
		9	4	1	6	2	8	3	7
		7	2	8	5	1	3	6	4
		5	6	3	7	4	9	8	2

दिव्यांग शिविरों में 150 दिव्यांगजनों को जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र

संवाददाता
देहरादून। जनपद में आयोजित विशेष दिव्यांग शिविरों में 150 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। आज यहां जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की पहल पर दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा उन्हें आवश्यक सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जनपद में आयोजित विशेष दिव्यांग शिविरों में 150 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। साथ ही, पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उनका चिह्नीकरण तथा यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिडियाल ने बताया कि अक्टूबर में देहरादून के विकासखंडों एवं क्षेत्रों में चार विशेष दिव्यांग शिविर आयोजित किए गए। इनमें 21 अक्टूबर को विकासखंड रायपुर के अंतर्गत गांधी शताब्दी अस्पताल में आयोजित शिविर में 31 व 22 अक्टूबर को विकासखंड डोईवाला परिसर में 39 तथा 23 अक्टूबर को राजकीय इंटर कॉलेज मेहूवाला परिसर (शिमला बाईपास) में 26 और 26 अक्टूबर को रियांश रिजॉर्ट, शिमला बाईपास रोड, समीप सींगनिवाला, शेरपुर



में आयोजित शिविर में 54 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शिविरों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के सहयोग से किया गया। शिविरों में दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दिव्यांगता की जांच की गई तथा निध रित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री दिव्यांग सहायता केंद्र के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत पात्र दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित

किया गया। दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदकों द्वारा यूडीआईडी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। इसके आधार पर संबंधित चिकित्सकों द्वारा दिव्यांगता की जांच की जाती है तथा चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में विशेष शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर स्वास्थ्य परीक्षण, प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।

स्कूलों में बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

अल्मोड़ा(आरएनएस)। बच्चों की सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा और शारदा पब्लिक स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा की ओर से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के निर्देशों पर सुरक्षित बचपन

अभियान के तहत इन शिविरों का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित शिविरों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो. याकूब, प्राधिकरण की सचिव अनामिका सिंह और न्यायिक मजिस्ट्रेट नवल सिंह बिष्ट ने विद्यार्थियों को बच्चों के कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को नालसा की

मेरा बचपन मेरा अधिकार, बोलो बताओ बचाओ% योजना-2०24 के तहत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाँक्सो), यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, असुरक्षित स्पर्श, शिक्षा एवं समानता के अधिकार और आत्म सुरक्षा के बारे में बताया गया। साथ ही मानसिक उत्पीड़न की पहचान, निःशुल्क कानूनी सहायता और साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया।

जागरूकता अभियान-बच्चों को बताए बाल अधिकार और साइबर सुरक्षा के गुर

संवाददाता
देहरादून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा संचालित ‘सुरक्षित बचपन जागरूकता अभियान’ के तहत नेहरू कॉलोनी स्थित स्टारलैंड विद्यालय में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

आज यहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा संचालित ‘सुरक्षित बचपन जागरूकता अभियान’ के तहत नेहरू कॉलोनी स्थित स्टारलैंड विद्यालय में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। अपर जिला जज पंचम अंजली बेंजवाल के नेतृत्व में आयोजित शिविर में छात्र-छात्राओं को बाल अधि कारों, बाल संरक्षण तथा बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

इस दौरान उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श की पहचान, साइबर सुरक्षा तथा किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार की स्थिति में



सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। किसी भी अप्रिय घटना अथवा समस्या की स्थिति में बिना झिझक अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। शिविर में बच्चों को आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में हेल्प डेस्क स्थापित की गई, जिसके माध्यम से छात्र-छात्राओं को अपनी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं के संबंध में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर

आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। इसके साथ ही अपर जिला जज अंजली बेंजवाल ने विद्यालय की प्रधानाचार्या को निर्देशित किया कि बच्चों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय में दो महिला और दो पुरुष शिक्षक-शिक्षिकाओं का पैनल गठित कर स्थायी हेल्प डेस्क स्थापित की जाए। शिविर में साइबर सेल से शिल्पा सैनी, जिला बाल संरक्षण इकाई से रश्मि बिष्ट, पैनल अधिवक्ता नूपुर मित्तल, प्राविधिक कार्यकर्ता कुलवीर सिंह तड़ियाल एवं किशोर जोशी सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, शिक्षक तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के 26 जिला अध्यक्षों के नामों की सूची जारी

संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के 26 जिला अध्यक्षों के नामों की सूची जारी कर दी है।

आज यहां कांग्रेस सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग के अध्यक्ष अभिनव थापर ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देशानुसार कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग में नियमानुसार जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया गया है। जिसमें पुरोला से विष्णु चरण सिंह को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही चमोली से राम दयाल, कोटद्वार से वरूण नेगी, कोटद्वार नगर से पंकज नेगी, पौड़ी गढवाल से उपेन्द्र रावत, टिहरी गढवाल से नवीन सेमवाल, रूद्रप्रयाग से कर्मवीर सिंह कुंवर, देवप्रयाग से रामलाल नौटियाल, हरिद्वार नगर से अरूण चौहान, परवादून से श्रीमती रेखा कांडपाल सती, पछवादून से जगपाल गुसाईं, काशीपुर नगर से शहदान इकबाल, हल्द्वानी नगर से कौशलेन्द्र भट्ट, नैनीतालसे पवन कुमार, अल्मोडा से भुवन कुमार पांडे, बागेश्वर से धीरज कुमार, पिथौरागढ़ से त्रिभुवन चुफाल, डीडीहाट से हिमांशु चुफाल, गंगोत्री, उत्तरकाशी से दीपक रावत, हरिद्वार ग्रामीण से अथर अंसारी, रूडकी महानगर से गौरव ठाकुर (प्रधान), रूडकी ग्रामीण से विकास कर्णवाला, देहरादून नगर से गुरचरण कौशल, रानीखेत से विजय सिंह कराकोटि, चम्पावत से नवीन पाण्डेय व रूद्रपुर महानगर से विकास विश्वास को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

‘लोकतंत्र’ की लड़ाई में ‘नैरेटिव’...

◀ पृष्ठ 2 का शेष

केवल प्रतिद्वंद्वी को घेरने में लगे हैं।

भाजपा की इस रणनीति का तात्कालिक लक्ष्य विपक्ष के नैरेटिव की काट तैयार करना और राजनीतिक बहस में अपनी पकड़ मजबूत करना है। लेकिन इसका दीर्घकालिक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अभियान जनता के बीच कितना विश्वसनीय साबित होता है। यदि पार्टी केवल विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाती है, तो राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। यदि वह तथ्यों के आधार पर सवालों का जवाब देती है, तो संस्थागत भरोसे की बहस को मजबूती मिल सकती है। विपक्ष के लिए भी यही कसौटी लागू होती है। केवल आरोपों की तीव्रता बढ़ाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति भरोसा मजबूत नहीं किया जा सकता। उसे स्पष्ट प्रमाण, जिम्मेदार राजनीतिक भाषा और संवैधानिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी होगी।

फिलहाल भाजपा ने संदेश दिया है कि वह वोट चोरी के आरोपों को विपक्ष का एकतरफा राजनीतिक हथियार नहीं बनने देगी। लेकिन इस लड़ाई का सबसे अहम सवाल यही है। क्या जवाबी अभियान आरोपों का शोर बढ़ाएगा या उन सवालों के तथ्यात्मक उत्तर सामने लाएगा, जिनसे लोकतंत्र में जनता का भरोसा जुड़ा है? क्योंकि अंततः लोकतंत्र की लड़ाई में नैरेटिव कुछ समय के लिए राजनीतिक बढ़त दिला सकता है, लेकिन स्थायी विश्वसनीयता का आधार तथ्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही से ही तैयार होता है।

उत्तराखंड पुलिस को मिला नया ध्वज..

◀ पृष्ठ 1 का शेष

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आगामी 6 नवंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस को प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रपति पुलिस कलर’ से अलंकृत किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तराखण्ड पुलिस के जवान नवीन सेरेमोनियल वर्दी में परेड में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखण्ड पुलिस अपनी नवीन पहचान के साथ जनसेवा, अनुशासन, दक्षता और कर्तव्यनिष्ठा के नए मानक स्थापित करेगी।

उत्तराखण्ड पुलिस के नवीन प्रतीक चिह्न में अशोक स्तंभ, ‘सत्यमेव जयते’, स्वर्णिम लॉरेल रीथ, हिमालय एवं नदी को समाहित किया गया है, जो राष्ट्रीय गौरव, सत्य, न्याय, उत्कृष्टता और उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक पहचान को दर्शाते हैं। पूर्व प्रचलित तीन रंगों वाले क्षैतिज पुलिस ध्वज के स्थान पर गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि वाला नवीन ध्वज अपनाया गया है, जिसके मध्य नया पुलिस प्रतीक चिह्न तथा लाल एवं स्वर्णिम किनारे शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्दी पर प्रयुक्त होने वाले फॉर्मेशन साइन, ईसिगिन्या और क्रैस्ट को भी नवीन प्रतीक चिह्न के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया गया है। इसके साथ ही पारंपरिक खाकी परिधान में बहुरंगी सेरेमोनियल सैश, अलंकरण एवं विशिष्ट परेड संबंधी साज-सज्जा को शामिल करते हुए सेरेमोनियल वर्दी को नया स्वरूप दिया गया है।

उत्तराखण्ड पुलिस के ध्वज का अनावरण पूर्व में 4 अप्रैल 2008 को हुआ था। बदलती चुनौतियों और पुलिस बल के बढ़ते दायित्वों के अनुरूप नवीन गौरव चिह्नों एवं प्रतीकों को तैयार किया गया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त विवरण के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा 21 अक्टूबर 2026 को नवीन स्वरूप को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, महानिदेशक पी.वी.के. प्रसाद, महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा अभिनव कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉ. वी. मुरुगेशन, सचिव दिलीप जावलकर, आर. राजेश कुमार, पंकज पांडेय, पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती रिधिम अग्रवाल सहित शासन एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गुरुकुल विवि में रजिस्ट्रार संग मारपीट

संवाददाता

हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के साथ मारपीट के मामले में छात्र प्रतिनिधि सोकेन्द्र बालियान ने गहरी चिन्ता व्यक्त की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

मिली जानकारी के अनुसार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों द्वारा रजिस्ट्रार के साथ कथित मारपीट की घटना पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र के विद्यार्थी व छात्र प्रतिनिधि सोकेन्द्र बालियान ने गहरी चिन्ता जताई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में हिंसा की घटना अत्यंत दुःखद और चिन्ताजनक है। विश्वविद्यालय में लगातार सामने आ रहे विवाद, अशांति और अव्यवस्था के मामले संस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोकेन्द्र बालियान ने कहा कि शिक्षा के केंद्र में संवाद, अनुशासन, सहिष्णुता और वैचारिक असहमति का सम्मान होना चाहिए। किसी भी विवाद का समाधान मारपीट से नहीं, बल्कि संवैधानिक, लोकतांत्रिक और संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि देश की गौरवशाली शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी प्रतिष्ठा और गरिमा बनाए रखना प्रशासन, कर्मचारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों सहित पूरे गुरुकुल परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बालियान ने विश्वविद्यालय की मौजूदा



शिक्षा के मंदिर में हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण: बालियान

परिस्थितियों पर चिन्ता जताते हुए कहा कि विद्यार्थी, स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारी और शिक्षक विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों की लंबित मांगें, शिक्षकों एवं फैकल्टी का विश्वविद्यालय छोड़ना, निलंबन की घटनाएं और लगातार बढ़ते विवाद चिन्ता का विषय हैं। इन परिस्थितियों का असर विद्यार्थियों के भविष्य और शैक्षणिक माहौल पर पड़ सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं कि विवाद संवाद और समाधान के बजाय मारपीट तक पहुंच रहे हैं? पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष समीक्षा कर कारणों का पता लगाने और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है।

सोकेन्द्र बालियान ने रजिस्ट्रार के साथ हुई कथित मारपीट की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने, घायल व्यक्ति को उचित चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा प्रशासन एवं कर्मचारी संगठनों के बीच तत्काल सकारात्मक

संवाद शुरू करने की मांग की। साथ ही स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का न्यायसंगत समाधान करने और शिक्षकों, फैकल्टी के विश्वविद्यालय छोड़ने, निलंबन तथा अन्य विवादों की पारदर्शी समीक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन और सामान्य व्यवस्था बहाल करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। उद्देश्य किसी व्यक्ति, संगठन या प्रशासन का विरोध करना नहीं, बल्कि गुरुकुल की गरिमा, शिक्षा की गुणवत्ता, कर्मचारियों के सम्मान और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। बालियान ने कहा कि आज की घटना पर शब्द भी मानो निःशब्द हैं। आखिर कब सुध रेंगे गुरुकुल के हालात, कब थमेगा अव्यवस्था और विवादों का दौर और कब लौटेगा गुरुकुल का खोया हुआ गौरव? गुरुकुल बचेगा, तभी उसका गौरवशाली इतिहास बचेगा।

गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाने को लेकर मोर्चा लड़ेगा: नेगी

संवाददाता

विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएनवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत लगभग 5000 अतिथि शिक्षकों का भविष्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के नकरापन की वजह से अंधकारमय हो रहा है, लेकिन इन्होंने कभी गंभीरता से इन टीचर्स के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। नेगी ने कहा कि इन अतिथि शिक्षकों को रू. 25000 मानदेय दिया जा रहा है,



जोकि नाकाफो है एवं इसके साथ-साथ इन अतिथि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाशों का वेतन (मानदेय) भी नहीं मिलता। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर इन कार्मिकों को न तो ईपीएफ की सुविधा मिलती है और न ही ईएसआई कीद्विभागीय मंत्री द्वारा रस्म अदायगी हेतु शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने

का निर्देश दिया गया था, लेकिन आज तक अमल नहीं हो पाया।

नेगी ने कहा कि 25000 रुपए में ये अतिथि शिक्षक अपने घरों से 100-200 किलोमीटर दूर अति दुर्गम इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलता। मोर्चा इन अतिथि शिक्षकों का मानदेय कम से कम 40000 रुपए करने व अन्य सुविधाएं दिलाने को लेकर लड़ाई लड़ेगा एवं मामले को सरकार के समक्ष भी रखेगा। पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह व प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद थे।

भव्य बाल मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक पुण्डीर

हमारे संवाददाता

देहरादून। सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर आज ग्राम चाँदपुर स्थित अनुनाद पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित भव्य बाल मेले में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर विधायक पुण्डीर ने दीप प्रज्ज्वलित कर बाल मेले का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा विधायक का शॉल ओढ़ाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत और सम्मान किया गया।

बाल मेले के दौरान विधायक ने विद्यालय के नन्हे-मुन्हे विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए कला एवं शिल्प (आर्ट एंड क्राफ्ट) तथा विज्ञान प्रदर्शनी के विभिन्न मॉडलों और रचनात्मक प्रस्तुतियों का अवलोकन किया। विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार के माध्यम से विभिन्न विषयों



पर आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक मॉडल प्रस्तुत किए। बच्चों की प्रतिभा, रचनात्मकता और उनके प्रयासों को देखकर विधायक ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर ने कहा कि बाल मेले जैसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे मंच विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता प्रदर्शित करने के साथ-साथ नई-नई चीजें सीखने, प्रयोग करने तथा अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर

प्रदान करते हैं। विधायक ने विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकगण एवं आयोजकों को इस सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ रचनात्मक एवं व्यावहारिक गतिविधियों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें निरंतर सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में सोमदत्त त्यागी निदेशक शिवालिक अकादमी सेलाकुई, कर्नल कदीर हुसैन निदेशक ब्राइट एंजल्स स्कूल विकासनगर, सुमन डोगरा अध्यक्ष अनुनाद पब्लिक स्कूल, प्रधानाचार्या सुनीता रावत, निदेशक फतेह सिंह रावत सहित विद्यालय के शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम में किया प्रतिभाग पीआरडी जवानों का बढ़ेगा मानदेय, प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनेगा मुख्यमंत्री खेल क्लब

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए घोषणा की कि पीआरडी जवानों के मानदेय को बढ़ाया जायेगा।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवेलियन ग्राउंड, देहरादून में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने दौड़ में शामिल युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उनका उत्साहवर्धन करते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं, खिलाड़ियों एवं प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मानदेय वृद्धि के संबंध में जल्द ही बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में



मुख्यमंत्री खेल क्लब का गठन किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने देहरादून के आमवाला स्थित युवा केंद्र से सटी रिक्त भूमि को युवा कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर मिनी

स्टेडियम एवं अग्निवीर प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इससे युवाओं को खेल सुविधाओं के साथ ही सेना में भर्ती की तैयारी के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी दृढ़

इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता से देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत आधार प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न रियासतों का एकीकरण कर सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सबसे पहली पहचान भारतीय होने की है। यही भावना हमें आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए मिलकर कार्य करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से सरदार पटेल के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि 'रन फॉर यूनिटी' जैसे आयोजन सरदार पटेल के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण

माध्यम हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदरीनाथ धाम से लौटते समय जोशीमठ क्षेत्र में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। मुख्यमंत्री ने भगवान बदरी विशाल से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एवं खजाना दास, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल, विधायक बृजभूषण गैरोला, उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष कुलदीप बुटोला, उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, निदेशक खेल श्रीमती दीप्ति सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को घंटाघर, देहरादून स्थित भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व से देश की रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा सरदार पटेल ने 560 से अधिक रियासतों के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाकर एक सशक्त भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा देश के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरकार पटेल के कार्यों का प्रत्येक भारतवासी सदैव याद रखेगा इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजाना दास, मेयर सौरभ थपलियाल एवं अन्य लोग मौजूद रहे।



घायल हाथी को उसके झुंड से मिलाया

हमारे संवाददाता

देहरादून। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक सुखद सफलता के तहत, उत्तराखंड के पीपल पड़ाव वन रेंज में एक गहरे गड्ढे में फँसे लगभग आठ वर्षीय जंगली हाथी को उत्तराखंड वन विभाग और वाइल्डलाइफ एसओएस के संयुक्त प्रयासों से बचाया गया, उसका उपचार किया गया और अंततः उसे उसके झुंड से मिलने में सफलता मिली।

25 अक्टूबर की रात इस हाथी को लगभग एक मीटर गहरे गड्ढे से बाहर निकाला गया था। हालाँकि, सुरक्षित बाहर निकाले जाने के बावजूद वह स्वयं खड़ा नहीं हो पा रहा था। वन विभाग की पशु चिकित्सा टीम ने उसका उपचार शुरू किया और उसकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी। बाद में, अतिरिक्त विशेषज्ञता और सहायता के लिए वाइल्डलाइफ एसओएस के विशेषज्ञों को भी इस प्रयास में शामिल किया गया।

वाइल्डलाइफ एसओएस की एक टीम घटनास्थल पर पहुँची और वन विभाग के पशु चिकित्सकों के साथ मिलकर हाथी की स्थिति का आकलन किया तथा आगे के उपचार की योजना बनाई। जाँच में उसकी पीठ के ऊपरी हिस्से में सूजन पाई गई। एक्स-रे में कोमल ऊतकों में चोट की आशंका जताई गई, जिसमें रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से के प्रभावित होने की संभावना भी थी। हाथी अपने चारों पैरों को हिला पा रहा था, लेकिन अगले पैरों पर शरीर का भार नहीं संभाल पा रहा था और स्वयं खड़ा होने में असमर्थ था।

वन विभाग की पशु चिकित्सा टीम के साथ मिलकर काम करते हुए, वाइल्डलाइफ एसओएस के विशेषज्ञों ने हाथी को आवश्यक सहायक उपचार प्रदान किया। इसमें शरीर में पानी की कमी दूर करने के लिए तरल पदार्थ देना, प्रभावित हिस्से पर लेजर थेरेपी, दर्द

प्रबंधन और घाव की ड्रेसिंग शामिल थी। जेसीबी और स्लिंग की मदद से हाथी को खड़ा करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन शुरुआती कोशिश में वह अपने शरीर का भार संभालने में असमर्थ रहा।

उपचार और लगातार निगरानी के दौरान हाथी की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत दिखाई देने लगे। उसने लगभग 8-10 किलोग्राम हरा चारा और 15-20 लीटर पानी का सेवन किया। इसके बाद जेसीबी और स्लिंग की मदद से किए गए एक अन्य प्रयास में हाथी बिना किसी सहारे के स्वयं खड़ा होने में सफल रहा। हालाँकि, उसके दाहिने अगले पैर में सूजन और लंगड़ाहट देखी गई, जिसके लिए पशु चिकित्सा टीम ने आवश्यक उपचार और निगरानी जारी रखी। उसे हरा चारा और गन्ना भी दिया गया। एक बेहद उत्साहजनक घटनाक्रम में, हाथी बाद में अपने झुंड की ओर चला गया और उससे जा मिला।

स्व. इंदिरा गांधी एवं लौह पुरुष स्व. पटेल को कांग्रेसियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

हमारे संवाददाता

देहरादून। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, देहरादून में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का देश के निर्माण, राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अतुलनीय योगदान रहा है। श्रीमती स्व. इंदिरा गांधी ने अपने दृढ़ नेतृत्व, साहसिक निर्णयों

और दूरदर्शी सोच से भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त पहचान दिलाई। वहीं सरदार पटेल ने अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता एवं दृढ़ इच्छाशक्ति से देश की रियासतों का एकीकरण कर मजबूत भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि हम सभी को इन महान विभूतियों के आदर्शों, विचारों और राष्ट्र के प्रति समर्पण से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इन दोनों महान नेताओं के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर कुछ कहना सूरज को दीपक

दिखाने के समान है। उनका योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व इतिहास में भी उनका विशिष्ट



स्थान है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने दृढ़ संकल्प और नेतृत्व क्षमता से भारत को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई, वहीं सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता और अदम्य इच्छाशक्ति से

देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ किया। आज आवश्यकता है कि हम उनके विचारों को आत्मसात करते हुए देश की एकता, भाईचारे और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करें।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संगठन राजेंद्र सिंह भंडारी, प्रदेश, पूर्व विधायक राजकुमार, उपाध्यक्ष सुजाता पॉल, प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद, महामंत्री अश्विनी बहुगुणा, महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी, प्रदेश महामंत्री अभिषेक सिंह, गरिमा माहरा दशौनी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ अध्यक्ष मदनलाल, सुरेंद्र रांगड़, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटेड 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार
समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटेर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।